

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
पन्तनगर, उधमसिंह नगर।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 29 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 'प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान' योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015, शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17.11.2015 एवं आपके पत्र संख्या: सीटीई/आयोजनागत/2015-16/332 दिनांक 18 दिसम्बर 2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजनान्तर्गत 'अनुदान संख्या 30' में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00लाख को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि से कॉलेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर नियमानुसार क्रय कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. पूर्व से इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए छात्र-छात्राओं को पुनः इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा तथा लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर को उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.04.2015 एवं दिनांक 17.11.2015 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. फर्नीचर क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
9. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/ वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त अनुदान का देयक कॉलेज के निदेशक/ वित्त अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में के 'अनुदान संख्या 30 के 'आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2203-तकनीकी शिक्षा-00 / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-00-03-पंत कालेज आफ टैक्नोलॉजी, पन्तनगर को सहायक के मानक मद '20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 01.04.2015 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1603303425 के अन्तर्गत तथा दिनांक 01.04.2015 व शासनादेश दिनांक 17.11.2015 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 389 (1)/XLI(1)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पन्तनगर।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव।